Government of India
Ministry of Drinking Water & Sanitation

Subject: Monthly summary for the month of December, 2018 in respect of Ministry of Drinking Water and Sanitation

A. **Swachh Bharat Mission (Gramin)**

Workshop on ODF Sustainability

Workshop on Capacity Building and Training of PRIs on ODF Sustainability was organized on 20th December, 2018 at India Habitat Centre, New Delhi. The Workshop was attended by State Secretaries/Mission Directors/NIRD/SIRDs/ Development Partners. A total of 50 participants attended the Workshop. The plan on training role out was discussed in details.

Another Workshop on ODF Sustainability Module Development was organized on 26th-28th December, 2018 at Conference Room, MDWS, New Delhi.

GOBAR-Dhan Scheme

A meeting to discuss the progress of GOBAR-Dhan projects was held with all States on 28.12.2018 in the Ministry. Some of the States such as Madhya Pradesh and Kerala made their presentations, detailing the progress made, institutional frameworks, best practices and the bottlenecks, the States have been facing in its implementation. They also made certain recommendations. All the States were asked to give their views on the extant policy, projects undertaken, IMS issue and to suggest way forward so as to give push to the scheme to achieve its objectives.

Meeting with the High Commissioner, Gambia

Secretary held a meeting with the High Commissioner from the Republic of Gambia. The meeting was in continuation to discussion held during the Mahatma Gandhi International Sanitation Conference and role of India in assisting other countries in becoming Open Defecation Free.

Review of the progress of Swachh Bharat Mission

i. Video Conference with ACS/Principal Secretaries/Secretaries and Mission Directors In-charge of Rural Sanitation in all the States organized on 19th December, 2018 at Conference Room, MDWS, New Delhi to discuss the pending issues of LOB and geotagging of toilets.
ii. Video Conference with ACS/Principal Secretaries/Secretaries -In-charge of Rural Sanitation in the States of Assam, Bihar, Jharkhand, Karnataka, MP, UP and DMs was organized on 18th December, 2018 at Conference Room, MDWS, New Delhi to discuss the issues of ODF verification of villages.
iii. A video conference was conducted with the Zila Swachh Bharat Preraks on 4 December 2018. The agenda of the conference was to gather feedback for the Management Information System (MIS) and improve it further

(B) National Rural Drinking Water Programme

Review of NRDWP in Gujarat

A review of the NRDWP program was held in Gujarat on 15th December 2018. Along with the review of the program at the state, the Secretary also visited a community water supply scheme in Shinai gram panchayat in the Kutch region.

Meeting with States on progress of NRDWP

A series of meetings was held from 21st to 24th December 2018 with all states to discuss the progress that was made under NRDWP. The meeting was attended by Chief Engineers and IMIS coordinators of the respective states. The discussion during the meeting was largely focused on unspent balances, geotagging of assets and registration of agencies on PFMS.

Review of Progress for Border Infrastructure

A review was held on water supply for rural water supply infrastructure. Proposals amounting to Rs. 495 Cr for rural water supply in border outposts have been reviewed and forwarded to the Ministry of Home Affairs for further action and implementation.

12th Techno Economic Review Committee

The 12th Techno-Economic Review Committee (Apex Committee) meeting was held on 27th December, 2018 under the chairmanship of Secretary (DWS). The meeting discussed the following:

- Funding and covering left out habitations under National Water Quality Sub Mission
- Setting a time limit on completion of works in the left out habitation to March 2021 and directing states to submit proposals on or before 31st January 2019.
- States to go for retro-fitting of water purification plants in existing PWS in left out habitations

****

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संबंध में दिसम्बर, 2018 माह का मासिक सारांश।

क. **<u>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)</u>**

<u>ओडीएफ स्थायित्व पर कार्यकलाप</u>

ओडीएफ स्थायित्व पर पीआरआई के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर एक कार्यशाला दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राज्य सचिवों/मिशन निदेशकों/एनआईआरडी/एसआईआरडी/विकास हिस्सेदारों ने भाग लिया। कुल 50 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया। प्रशिक्षण की भूमिका संबंधित योजना पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

ओडीएफ स्थायित्व मॉड्यूल विकास पर एक और कार्यशाला 26-28 दिसम्बर, 2018 को सम्मेलन कक्ष, एमडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

<u>गोबर-धन स्कीम</u>

गोबर-धन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के साथ एक बैठक 28.12.2018 को मंत्रालय में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश और केरल जैसे कुछ राज्यों ने अपनी प्रस्तुतियां दी जिनमें प्रगति, सांस्थनिक ढांचा, सर्वोत्तम रीतियों और राज्यों के समक्ष कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं का ब्यौरा था। उन्होंने कुछ सिफारिशों भी कीं। सभी राज्यों से कहा गया कि मौजूदा नीति और आरंभ की गई परियोजनाओं, आईएमएस मुद्दे पर अपने विचार रखें और आगे के लिए सुझाव दें ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्कीम को और बढ़ावा दिया जा सके।

<u>उच्चायुक्त, गाम्बिया के साथ बैठक</u>

सचिव ने रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया के उच्चायुक्त के साथ एक बैठक की। यह बैठक, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के दौरान अन्य देशों को खुले में शौच मुक्त बनाने में सहायता करने में भारत की भूमिका पर चर्चा के अनुक्रम में थी।

स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा

i. एलओबी के लम्बित मामलों पर चर्चा करने और शौचालयों के जियो टैंगिंग के लिए सभी राज्यों के एसीएस/प्रधान सचिवों/सचिवों और मिशन निदेशकों प्रभारी, ग्रामीण स्वच्छता के साथ विडियों कॉन्फ्रेंस 19 दिसम्बर, 2018 को सम्मेलन कक्ष, एमडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली में आयोजित की गयी।
ii. गांवों के ओडीएफ सत्यापन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए असम, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एसीएस/प्रधान सचिवों/सचिवों- ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी और डीएम के साथ विडियों कॉन्फ्रेंस 18 दिसम्बर, 2018 को सम्मेलन कक्ष, एमडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
iii. जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों के साथ एक विडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 को आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस का एजेन्डा, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए फीडबैक इकट्ठा करना तथा इसे और बेहतर बनाना था।

ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

गुजरात में एनआरडीडब्ल्यूपी की समीक्षा

एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम की समीक्षा दिनांक 15 दिसंबर, 2018 को गुजरात में आयोजित की गई। राज्य में इस कार्यक्रम की समीक्षा के साथ-साथ, सचिव ने कच्छ क्षेत्र में शिनाई ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक जल आपूर्ति स्कीम का भी दौरा किया।

एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति पर राज्यों के साथ बैठक

सभी राज्यों के साथ दिनांक 21 से 24 दिसंबर, 2018 तक कई बैठकें आयोजित की गईं ताकि एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत हुई प्रगति पर चर्चा की जा सके। इस बैठक में मुख्य अभियंताओं तथा संबंधित राज्यों के आईएमआईएस समन्वयकों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान अव्ययित बकायों, परिसंपत्तियों के भू-अंकन (जीयोटैगिंग) तथा पीएफएमएस पर एजेंसियों के पंजीकरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

सीमा अवसंरचना (बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर) पर हुई प्रगति की समीक्षा

ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना हेतु जल आपूर्ति पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बोर्डर आउटपोस्ट में ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु 495 करोड़ रूपए की राशि के प्रस्तावों पर समीक्षा की गई तथा आगे की कार्रवाई एवं क्रियान्वयन हेतु गृह मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया।

<u>12वां टेक्नो इकोनॉमिक रिव्यू कमेटी</u>

12वीं टेक्नो-इकोनॉमिक रिव्यू कमेटी (शीर्ष समिति) की बैठक सचिव (डीडब्ल्यूएस) की अध्यक्षता में दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को आयोजित की गई, इस बैठक में निम्नलिखित पर चर्चा की गई:

- राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन के तहत छूट गए बसावटों को निधियन उपलब्ध कराना तथा उन्हें कवर करना
- मार्च, 2021 तक छूट गई बसावटों में कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना तथा राज्यों को यह निदेश देना कि दिनांक 31 जनवरी, 2019 को अथवा उसके पूर्व प्रस्तावों को प्रस्तुत करना।
- राज्यों को छूट गई बसावटों में मौजूदा पीडब्ल्यूएस में जल शोधन संयत्रों की नए रेट्रो-फिटिंग करना।